

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में, *

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ११ मार्च 2011

विषय:-मै० हीरो होण्डा मोटर्स लि० को जिला एवं तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद में ट्रांसपोर्ट यार्ड की स्थापना हेतु कुल 2.049 है० भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4/भूमि व्यवस्था-भूमि कय दि०-27.4.2009 एवं पत्र सं०-952/भूमि व्यवस्था-10 दि०-28.1.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै० हीरो होण्डा मोटर्स लि० को जिला एवं तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद में ट्रांसपोर्ट यार्ड की स्थापना हेतु कुल 2.049 है० भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के परामर्श के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजनार्थ यथा मै० हीरोहोण्डा मोटर्स बाइको के लदान हेतु अलग से ट्रांसपोर्ट यार्ड के निर्माण और उक्त यार्ड में कन्टेनर एवं हैवी ट्रकों की पार्किंग के प्रयोजनार्थ) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि यह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा

जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट यार्ड एवं पार्किंग आदि के लिए समस्त अधरस्थापना सुविधाएँ कंपनी द्वारा स्वयं जुटाई जाएंगी एवं राज्य का इस संबंध में कोई सहयोग नहीं होगा।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

6- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

7- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि अकृषक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार अकृषक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ट्रांसपोर्ट यार्ड निर्माण के प्रयोजन हेतु प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण/स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- ट्रांसपोर्ट यार्ड हेतु क्रयानुबन्धित भूमि पर कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के उत्पाद विनिर्माणक गतिविधि नहीं की जायेगी, चूँकि यह भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है तथा इस भूमि पर कम्पनी को अपने उत्पादों के विनिर्माण पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

10- मै0 हीरोहोण्डा मोटर्स लि0 द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग ट्रांसपोर्ट यार्ड की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

12- किसी भी दशा में प्रस्तावित कंटेनरों को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

15— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

16— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डॉ० राकेश कुमार)
सचिव।

पृ०प०सं०- 264 /संगदिनांकित/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— अधिकृत हस्ताक्षरी, मै० हीरो होण्डा मोटर्स लि०, प्लॉट नं०-3, सेक्टर 10, आई०आई०ई० सिडकुल हरिद्वार।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बाडोनी)
अनुसचिव।